

## GeM प्लेटफॉर्म को पूर्णतः अपनाने वाला पहला राज्य- उत्तर प्रदेश

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश [गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस \(GeM\) प्लेटफॉर्म](#) को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

इस कदम से प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है, साथ ही नषिपक्ष व्यवहार को बढ़ावा मल्लिगा और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा।

### मुख्य बढि

- उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती नविदि प्रणाली में एकरूपता का अभाव था तथा उसका दुरुपयोग होने की संभावना थी।
  - GeM मानकीकृत नयिनों को लागू करके इन मुद्दों का समाधान करता है, जिससे उल्लंघन या खामियों की संभावना कम हो जाती है।
  - राज्य सरकार का लक्ष्य सभी राज्य वभिगों में GeM के उपयोग को बढ़ाना, अनुपालन सुनिश्चित करना और जवाबदेही बढ़ाना है।
  - **परदर्शति सफलता:**
    - उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्नरिमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 18 [अटल आवासीय वदियालयों](#) के लयि सामग्री खरीदने हेतु GeM का उपयोग कयि।
      - कक्षा 6 से इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्रों को शकिषा प्रदान करने वाले ये स्कूल अब [कोवडि-19 महामारी](#) के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने सहति अनुकरणीय शकिषण वातावरण प्रदान करते हैं।
  - **नीति सुधार और अनुपालन:**
    - **सखत दशिा-नरिदेश:** नीतियिँ ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस डिसिक्वरी बडि, क्वांटिटी-बेसड बडि और बोली मूल्यांकन (Bid Evaluations) के दौरान नमूनों के लयि अनावश्यक अनुरोध जैसी प्रथाओं पर रोक लगाती है।
      - सभी राज्य वभिगों को अपनी वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं का कम से कम 25% GeM के माध्यम से खरीदना होगा तथा ऐसा न करने पर जुरमाना लगाया जाएगा।
  - लघु उद्यमों के लयि समर्थन: नविदि पात्रता मानदंडों में ढील (जैसे, टर्नओवर और पछिला प्रदर्शन) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के लयि अवसर उत्पन्न करते हैं।
  - श्रमकि कल्याण प्रावधान: नीतियिँ में आउटसोर्स कर्मचारियिँ के लयि न्यूनतम मज़दूरी, [कर्मचारी भवषिय नधि \(EPF\)](#) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) लाभ अनविर्य कयि गया है।
    - सेवा प्रदाता नयिक्तिके बाद मनमाने ढंग से आउटसोर्स कर्मचारियिँ को नहीं बदल सकते, जिससे नौकरी में स्थरिता और नषिपक्षता सुनिश्चित हो सके।
  - मल्लिभगत-रोधी उपाय: मल्लिभगत या बोली (Bid) में हेराफेरी करने पर कठोर दंड लगाया जाता है, तथा मामले की सूचना GeM टीम को देने का प्रावधान है।
  - शकियत नविरण तंत्र: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचवि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समतियिँ समर्पति ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन संबंधी शकियतों की समीक्षा करती है।
- राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखण:
- GeM को अपनाने से शासन में पारदर्शति और जवाबदेही बढ़ाकर "[डजिटल इंडिया](#)" के दृष्टिकोण को बढ़ावा मल्लिगा।
  - यह मंच स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं को समर्थन प्रदान करता है तथा "[मेक इन इंडिया](#)" पहल के अनुरूप नषिपक्ष प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देता है।

### गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म

- GeM वभिनिन सरकारी वभिगों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षति सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुवधि प्रदान करता है।
- यह पहल वाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी।

- GeM का वर्तमान संस्करण अर्थात **GeM 3.0**, 26 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया था ।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिये ई-बिडिंग, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है, जिससे उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त होता है और सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाया जाता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/up-first-state-to-fully-adopt-gem-platform>

